RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 40 प्रति सोमवार, 10 फरवरी 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

दिल्ली में केजरीवाल की हार और भाजपा की जीत से अधिक खतरा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हैं

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

नई दिल्ली विधानसभा चुनाव से 08 फरवरी को पर्दा उठ गया। खास बात यह है कि सिर्फ पर्दा ही नहीं उठा बल्कि आम आदमी पार्टी और उसके मंत्री हार चुके हैं। चुनाव में हार जीत होती है, एक पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी को विपक्ष में बैठना ही होता है। लेकिन अब अगर बात की जाये भारतीय जनता पार्टी की तो यह भाजपा की यह जीत के पीछे कई प्रश्न मन में उठते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज तक जिस दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राज करती आई 27 साल तक भाजपा को सत्ता से विमुक्त रखा गया। अचानक उस पार्टी की हार राज्य के चुनावों में लगातार होती जीत कहीं न कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर सवालियां निशान खड़ा करती है। बतौर पत्रकार सवाल उठाना इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि अगर यही सिलसिला आगे भी रहा तो एक दिन ऐसा आयेगा जब पूरे देश में भाजपाई कमल

खिलेगा और देश में अराजकता का माहौल खड़ा होगा। बात चाहे दिल्ली की हो, मप्र, छग, राजस्थान की हो या फिर हरियाणा और अन्य राज्यों की। जहां-जहां भाजपा ने सत्ता पाई है उन राज्यों में धीरे-धीरे अराजकता का माहौल पनपता जा रहा है। यह माहौल लोकतंत्र के लिये खतरे की ओर इशारा करता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर देश की जनता लोकतंत्र में चुनाव की इस प्रक्रिया पर भरोसा करें भी तो कैसे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम भाजपा के पक्ष में आया है। बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली जबकि आम आदमी पार्टी इस बार 22 सीटों पर ही सिमट गयी। वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस के कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त तक हो गयी। दिल्ली चुनाव परिणाम सामने आने पर यह चर्चा भी छिड़ी है कि कांग्रेस ने 'आप' से बदला लिया और कई सीटों पर अरविंद केजरीवाल समेत उनके उम्मीदवारों की हार की वजह बनी। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत पर जनता के कारण हुई है। 27 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। किसी चुनाव में समान कारण वजह नहीं बनता। कई वजह होते हैं जिसके कारण परिणाम बदलता है। (शेष पेज 7 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी सुकमा जिले के लोगों को सौगात

205 करोड़ रुपए के 137 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का लक्ष्य है आगामी एक वर्ष में राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल दें। यही कारण है कि वे पूरी योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने में जुटे हुए हैं। राज्य के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद उसके क्रियान्वयन के लिये जमीनी स्तर पर कार्य पूरा करने का लक्ष्य अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह सक्रियता न सिर्फ राज्य की जनता के लिये एक शुभ संदेश है बल्कि राज्य के अंदर दीमक की तरह पनप रहे नकस्लवाद को खत्म करने की दिशा में भी एक सराहनीय पहल है। दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री साय ने सुकमा जिले में 205 करोड़ रुपये के 137 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। खास बात यह है कि यह वही जिला है जहां सबसे ज्याद नक्सलियों के होने की

आंशाका होती है और यह नक्सली प्रदेश की जनता और सेना के जवान तथा पुलिस जवानों के लिये खतरे से कम नहीं है। ऐसे में सरकार नक्सल विरोधी अभियान चलाकर इन्हें जड़ से समाप्त करने की योजना पर कार्य कर रही है।

कैंसर की तरह है माओवाद

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि माओवाद एक कैंसर की तरह है। कैंसर को समाप्त करना है तो इसकी जड़ पर प्रहार करना जरूरी होता है। माओवादी बस्तर के कुछ इलाकों में जोंक की तरह चिपक गये थे और यहां के स्थानीय लोगों को डरा-धमका कर शोषण कर रहे थे। ये स्थल उनके सबसे सुरक्षित पनाहगाह थे। हमने माओवादियों की माँद में घुसकर उन पर हमले का निर्णय लिया। हमारे सुरक्षाबलों के जवानों के अदम्य साहस से हमने इन माओवादियों का मुकाबला किया और उनको धूल चटाई। बीते एक साल में विभिन्न मुठभेड़ों में हमारे सुरक्षाबलों ने 230 से अधिक माओवादियों को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि माओवादी हिंसा ने बस्तर संभाग के साथ ही सुकमा जिले को भी हिंसा की आग में झोंक दिया था। इससे सुकमा जिले का विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ था।एक साल में हमारी सरकार ने सुकमा जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये और इस पर तेजी से क्रियान्वयन किया है। (शेष पेज 2 पर)

मध्य प्रदेश में शराब की सरकार या सरकार की शराब

क्या धार्मिक नगरों में शराबबंदी का असली मकसद अवैध शराब से कमाई के लिए उठाया गया कदम है?

-विजया पाठक

शराब बंदी आज के भारत में समाज उत्थान के लिए काफी जरूरी है। नशामुक्त समाज आदर्श राष्ट्र की कल्पना का पहला पड़ाव है। किन्तु देश में शराब सत्ताशीर्ष के लिए सबसे आसान अवैध पैसा कमाने का तरीका है। दरअसल मध्य प्रदेश में जो आंशिक शराब बंदी हुई है वो पैसे कमाने का जरिया नजर आ रहा है। इसका एक उदाहरण आज उज्जैन है, जहां पर सत्ता का परम आशीर्वाद लिए एक परिवार शराब से प्रतिदिन 15-20 लाख की कमाई कर रहा है, प्रत्येक बोतल से 40-50 रुपये इस परिवार के पास जाते हैं, वैसे भी शराब से संबंधित व्यापार से इनका पुराना नाता है। ऐसे में प्रदेश में 19 धर्म क्षेत्र सत्ता शीर्ष के लिए प्रतिदिन करोड़ों की आसान कमाई नजर आ रही है।

प्रदेश को नशामुक्त बनाने का

संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के 19 धार्मिक स्थलों पर पूर्ण शराब बंदी का फैसला किया है। शराब बंदी का यह फैसला लेकर मोहन यादव ने पूरे देश में खूब वाहवाही लूट तो ली है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शराब बंदी का यह फैसला सिर्फ 19 स्थानों पर ही क्यों लिया। (शेष पेज 2 पर)

क्या धार्मिक नगरों में शराबबंदी का असली मकसद अवैध शराब से कमाई के लिए उठाया गया कदम है?

(पेज 1 से जारी)

क्या सिर्फ इन्हीं 19 स्थानों में लोग शराब पीते हैं बाकी जिलों में शराब का उपयोग करने वाले लोगों, उनके परिवारों की चिंता कौन करेगा। उन लोगों के परिवार के लोगों की चिंता के बारे में मुख्यमंत्री यादव ने क्यों नहीं सोचा। मुख्यमंत्री का यह रवैया इस बात की ओर इशारा करता है कि मुख्यमंत्री यादव की शराबबंदी को लेकर कुछ और मंशा है। जबकि गुजरात में देखा जाए तो मोदी सरकार के समय से ही सही योजनाबद्ध ढंग से शराब बंदी का फैसला लेकर इसे बेहतर ढंग से लागू किया गया।

क्या काल भैरव की परंपरा तोड़ेंगे मुख्यमंत्री?

मध्यप्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल उज्जैन के काल भैरव मंदिर में भगवान शिव को प्रसाद के रूप में शराब भेंट करने की परंपरा है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री यादव काल भैरव की इस सनातनी परंपरा के साथ छेड़छाड़ कर शराब भेंट करने का दुस्साहस कर पाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार मुख्यमंत्री यादव का शराब बंदी का फैसला महज एक जुमला है जो उन्होंने प्रदेश की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री यादव अब इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं।

आबकारी नीति में बदलाव की तैयारी

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए आबकारी नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब सरकार ने कच्ची शराब के शौकीनों के लिए हल्के नशे वाली शराब लांच करने का फैसला किया है। यह शराब आम शराब के मुकाबले सस्ती होगी। वहीं प्रदेश के 38 जिले ऐसे होंगे, जहां पूरे शहर में शराब बिकेगी। इन जिलों में पहले की तरह शराब की बिक्री होगी। वहीं 17 जिलों यानि धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। इसके चलते इन नगरों से 47 शराब की दुकानों को 01 अप्रैल से बंद किया जाएगा। इससे सरकार को 450 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा।

शराब की नई वैरायटी, खोलो और पी जाओ

दूसरे राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश में अंडर प्रूफ शराब बेचने की तैयारी कर रही है। इसकी खासियत यह होगी कि यह बाजार में मौजूद शराब से सस्ती होगी। हालांकि यह हल्के नशे वाली शराब होगी। यह उन शौकीनों के लिए होगी, जो कच्ची शराब पीने के आदि होते हैं। जबकि यह सेहत के लिए हानिकारक होती है। वहीं राज्य सरकार ने नई वैरायटी के साथ नए बार खोलने का भी फैसला किया है। इसे बिना पानी मिलाए उपयोग किया जा सकेगा। यह रेडी टू ड्रिंक होगा। यह बीयर से अलग होगी। बार में रेडी टू ड्रिंक और बीयर दोनों उपलब्ध होंगी। इस तरह की शराब नीति से और लोग भी शराब की आदि हो जायेंगे। युवावर्ग इस नीति के मोह में आकर शराब पीने लगेंगे।

बार लाइसेंस फीस में कमी का फैसला

सरकार द्वारा नए खोले जा रहे नए बार में उद्यमियों को राहत देने के लिए सरकार ने बार के लाइसेंस फीस को कम रखने का फैसला किया है। हालांकि यह वह बार होंगे, जहां कम एल्कोहल वाली शराब यानी रेडी टू ड्रिंक और बियर ही उपलब्ध होगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे नए बीयर बार में उद्यमियों को कम लाइसेंस फीस के रूप में राहत मिलेगी। वहीं उपभोक्ताओं को भी सस्ती बीयर रेडी टू ड्रिंक मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि इससे लोग भी कम नशीले पदार्थ की तरफ आकर्षित होंगे। सवाल यह है मोहन सरकार सच में प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है या यह सिर्फ एक खानापूर्ति और रईस परिवारों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे शराब उद्यमी को फायदा पहुंचाकर सरकारी खजाने में घाटा होगा।

शराब से मौतों में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर

वैसे भी शराब से होने वाली मौतों में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है। इसके साथ ही शराब से होने वाली अप्रिय घटनाओं में बढ़ोत्री हो रही है। इसके बाद भी मोहन सरकार शराब को लेकर नई नीति लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में इजाफा होगा। जिसके लिए मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। मध्यप्रदेश में शराब कितनी घातक है इसका सबसे बड़ा प्रमाण है राज्य में पिछले छह सालों में हुई मृत्यु। बावजूद इसके प्रदेश में 07 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक लाख से अधिक छेड़छाड़, मारपीट आदि से जुड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। बावजूद इसके अगर यह सब देखने के बाद भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में नई शराब नीति लाने की योजना बना रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश और प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं होगा।

मध्यप्रदेश को नहीं मोह पाए हैं मोहन

मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने एक साल से ऊपर हो गया पर इस दौरान प्रदेश गर्त में ही जाता रहा। प्रदेश की खस्ताहाल हालत के जिम्मेदार मोहन यादव अपनी चाल, चरित्र और चेहरे से प्रदेश का मन नहीं मोह पाए हैं। झूठे वादे और घोषणाएँ की पोल इन्वेस्टर्स समिट में वैसे ही खुल गई, जहां 50 दिनों तक उद्योगों को पर्यावरण संबंधी अनुमति नहीं मिल पायी वहीं जिलेवार समिट में वहीं कंपनी और इनवेस्टर्स बार-बार देखे गए। अब जब कमाई के सीमित स्त्रोत बचे हैं तो व्यापारिक सोच रखने वाले सत्ता शीर्ष अब शराब से होने वाली कमाई को साधन बनाने के फिराक़ में है। उज्जैन में शराब का खेल तो पिछले 6 महीने से चल रहा है, जिसकी जानकारी चाहे तो प्रधानमंत्री भी ले सकते हैं। आंशिक शराब बंदी से निश्चित तौर पर राजस्व को तगड़ा झटका लगेगा। साथ ही शराब तो जनता के पास पहुंचेगी पर पैसा सरकारी खजाने में ना जाकर एक परिवार के पास जरूर जाएगा।

205 करोड़ रुपए के 137 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास

(पेज 1 से जारी)

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कड़ी में आज हमने यहां 205 करोड़ रुपए के 137 कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया है। इन कार्यों में 39 करोड़ रुपए की राशि के 82 कार्यों का लोकार्पण एवं 166 करोड़ रुपए के 55 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। इन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य सुकमा नगरपालिका में 83 करोड़ रुपए की लागत से जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन है। इसके साथ ही 14 करोड़ रुपए की राशि से केरलापाल से पोंगाभेज्जी मार्ग के निर्माण का भूमिपूजन भी हमने किया। उन्होंने कहा कि सुकमा में खेल अधोसंरचना बेहतर हो, इसके लिए 11 करोड़ रुपए की लागत से हम स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाने जा रहे हैं। इसका भी हमने आज भूमिपूजन किया है।

माओवाद प्रभावित इलाकों में कैंपों का विस्तार किया

मुख्यमंत्री साय ने सुनियोजित रणनीति के तहत हमने माओवाद प्रभावित इलाकों में कैंपों का विस्तार किया और सुरक्षा का नेटवर्क विस्तृत किया। अब माओवादी बहुत सीमित इलाके में सिमट गये हैं और बौखलाहट में हैं। इसके चलते वे कायराना हरकत कर रहे हैं। माओवादियों द्वारा हमारे जवानों के काफिले पर आईईडी ब्लास्ट की घटना में जो जवान शहीद हुए, वे बस्तर के माटीपुत्र ही थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सुकमा की इस धरती पर हम सब पुनः संकल्प लेते हैं कि माओवाद को जड़ से नष्ट

करेंगे। हमारे शहीद जवानों की शहादत का बदला लेंगे।

नेल्ला नार योजना आरंभ की

मुख्यमंत्री साय ने कैंपों के माध्यम से लोगों को सुरक्षा दिलाने के साथ ही विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने कैंप के पांच किमी की परिधि में आने वाले गांवों के विकास के लिए नियद नेल्ला नार योजना आरंभ की जिसके माध्यम से सभी बुनियादी सुविधाएं इन ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही है। जो माओवादी अपने लिए सबसे अच्छे हथियार, संचार के नये उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को इतने दहशत में रखा कि यहां के लोग टेलीविजन से भी दूर रहे। माओवादी कमांडर का गांव पूवर्ती विकास के मामले में कई बरस पिछड़ा हुआ था। लोगों ने बिजली नहीं देखी थी, टेलीविजन नहीं देखा। अब पूवर्ती गांव सोलर लाइट से रौशन है। आजादी के 78 साल बाद पहली बार दूरदर्शन लोगों ने देखा। यह लोगों के लिए चमत्कार की तरह था। ग्राम सालातोंग में 78 साल बाद बिजली आई है। बिजली के आने से यहां विकास का उजाला भी तेजी से फैला है। अब यहां के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। लोगों को आवागमन के लिए राहत हो, इसके लिए यहां पर हक्कुम मेल चलाई जा रही है। इन बसों के चलते लोगों का जीवन आसान हो गया है। स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचना आसान हो गया है।इस योजना के माध्यम से पहली बार लोगों के आधार कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड बने और किसान क्रेडिट कार्ड भी बने।

महतारी वंदन योजना का दिया लाभ

महतारी वंदन योजना के माध्यम से हम सुकमा जिले की 52 हजार 220 माताओं को हर महीने एक हजार रुपए की राशि अंतरित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 6000 से अधिक हितग्राहियों के लिए प्रधानमंत्री आवास की किश्त जारी कर दी है। हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर साढ़े 5 हजार रुपए कर दी है और 63 हजार से अधिक हितग्राहियों को अब तक 77 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर चुके हैं। बस्तर ओलंपिक में बस्तर संभाग के 1 लाख 65 हजार लोगों ने हिस्सा लिया।

आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हमें सिखाया कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान हैः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

आचार्य जी के उपदेश प्रकाश स्तंभ की तरहः पथ को आलोकित कर देती है सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणाः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हमें सिखाया कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। अगर हम अपनी संस्कृति को खो देते हैं तो विश्व के समक्ष हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती। आचार्य जी ने संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद आदि संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानवता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश हम सभी को दिया है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि स्मारक के भूमिपूजन और विनयांजलि समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जैन आचार्यों और मुनियों ने संपूर्ण देश को एकसूत्र में बांधने का कार्य किया है। जैन संतों और मुनियों ने उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक और बिहार के राजगीर से गुजरात के गिरनार तक हर जगह पैदल भ्रमण कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए त्याग और तपश्चर्या से सन्मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी ने एक कल्पवृक्ष की भांति जीवन जिया। उनके तप और त्याग से प्रत्येक क्षण देशवासियों को नई प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि आज इस स्थान पर सभी लोगों ने मिलकर आचार्य जी की भव्य समाधि का निर्माण करने का निर्णय लिया है, इसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भौतिक देह से भले ही हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके उपदेश हमें प्रकाश स्तंभ की तरह युगों युगों तक हमेशा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। आचार्य जी ने धर्म की रक्षा और राष्ट्र की मजबूती के लिए मीलों पैदल सफर तय किया। आहार-विहार का ऐसा संयम रखा जिसे सोचकर ही हम सब चकित रह जाते हैं। आचार्य जी ने करोड़ों लोगों को अपने जीवन से प्रेरणा दी। वे एक राष्ट्र संत थे और स्वदेशी के प्रति उनका गहरा अनुराग था। वे हमेशा कहते थे कि हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने पूज्य समता सागर जी महाराज और देशभर से आए सभी जैन मुनियों को प्रणाम करते हुए कहा कि संतों का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को सदैव मिलता रहे, ऐसी मेरी कामना है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी, लोकसभा सांसद संतोष पाण्डेय, विधायक डोंगरगढ़ हर्षिता स्वामी बघेल, जैन समाज के अशोक पाटनी, महोत्सव के अध्यक्ष विनोद बड़जात्या, श्रीकांत प्रभात जैन, विनोद जैन, मनीष जैन एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित समाज के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सभी विभागों में ई-आफिस का पूर्ण क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक करें सुनिश्चितः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार सुशासन को सशक्त बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में, 01 जनवरी 2025 को विभागीय सचिवों की बैठक में सभी विभागों और कार्यालयों में ई-ऑफिस को लागू करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिकांश फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से ही निपटाई जा रही हैं और सभी विभागों में इसका पूर्ण क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस के प्रशिक्षण की सुविधा देने की बात कही, ताकि सभी विभागों में इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। पहले इसे सामान्य प्रशासन विभाग में शुरू किया गया था और अब इसे मंत्रालय के सभी विभागों में विस्तारित कर दिया गया है। अब तक 16 विभागाध्यक्ष कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है और जिला स्तर पर भी इसे लागू करने की

प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सक्ती पहला ऐसा जिला है, जहां ई-ऑफिस पूरी तरह से लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों की गति, दक्षता और पारदर्शिता में अभूतपूर्व सुधार होगा। इस पहल से सरकारी प्रक्रियाओं में स्वचालन आएगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी, निर्णय लेने की गति तेज होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सभी विभागों में फाइलों की डिजिटल स्वीकृति सुनिश्चित की जाए, ताकि सरकारी कार्यों में अनावश्यक देरी समाप्त हो और प्रशासनिक निर्णयों को त्वरित रूप से लागू किया जा सके। राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "डिजिटल इंडिया" अभियान को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे राज्य की सभी सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, सुगम और त्वरित बनेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को सुशासन के प्रभावी उपकरण के रूप में अपनाया गया है, जिससे सरकारी सेवाएं तेजी से और आसानी से जनता तक पहुंचेंगी। ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन से फाइलों के अनुमोदन में लगने वाला समय कम होगा, जिससे प्रशासनिक निर्णयों को शीघ्र लागू किया जा सकेगा। इसमें फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और डुप्लिकेशन रोकने के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन की सुविधा शामिल है। कागजी कार्यवाहियों में कमी आने से सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और शासन अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगा। ई-ऑफिस प्रणाली से कागज, मानव संसाधन और परिवहन लागत में भी बचत होगी, जिससे सरकारी खर्चों में भी कमी आएगी।

जिले के शहरों में नियम विरुद्ध संचालित हो रहीं पैथालाजी लेब

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले के शहरों में इस समय नियमों विरुद्ध तरीके से पेथालाजी लेब का संचालन देखने को मिल रहा है। दिन पे दिन इनका भी मकडजाल झोलाछाप डाक्टरों की तरह फैलता जा रहा है। जबकि सरकारी मापदंड के अनुसार पेथालाजी लेब का संचालन सिर्फ डॉक्टर ऑफ मेडिसीयन या मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त पेथालाजी में डिग्रीधारी ही कर सकते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि पैथालाजी लेबों का संचालन धड़ल्ले से नियमों विरुद्ध करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो पेथालाजी जांच में सेम्पल वा जांच के समय एमडी मेडिसीएन का होना अनिवार्य होता है एवं उसकी उपस्थित में ही रिपोर्ट का वेरीफाइड होना अनिवार्य माना गया है लेकिन जिले के शहरों में डिप्लोमाधारी संचालकों के द्वारा मेडिसीएन की अनुपस्थित में बाहर से डिजीटल साईन अपलोड कराकर रिपोर्ट दी जा रहीं हैं। जो मान्य नहीं हैं। नरसिंहपुर जिले के अकेले गाड़रवारा शहर में 18 पेथालाजी लेब संचालित हैं जिनका पंजीयन नहीं हैं। पंजीयन हैं तो वह एमडी डाक्टर जबलपुर या भोपाल के हैं। सूत्रों ने बताया पूरे जिले में लगभग 100 पेथालाजी लेब संचालित नियमों विरुद्ध हो रही हैं। मरीजों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ की जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को केंद्रीय जेल नर्मदापुरम के बंदियों द्वारा बनाई पोर्ट्रेट भेंट

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नर्मदापुरम जिले के प्रवास पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ यादव को स्थानीय सर्किट हाउस में केंद्रीय जेल नर्मदापुरम के महिला एवं पुरुष बंदियो द्वारा बनाई वर्ली आर्ट पेंटिंग, मुख्यमंत्री का पोट्रेट एवं अन्य वस्तुओं से भरी टोकरी भेंट की। जिला जेल अधीक्षक संतोष सोलंकी एवं सहायक जेल अधीक्षक हितेश बंडिया द्वारा उक्त भेंट दी गई। वर्ली आर्ट पेंटिंग एवं पोट्रेट पेंटिंग महिला बंदी श्रीमती तबस्सुम एवं लाल बेन द्वारा बनाई गई थी। वहीं जेल में महिला बंदियो द्वारा संचालित अंजनी स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित गणेश जी की प्रतिमा, मोरिंगा पाउडर, आंवला अचार, मिक्स अचार, आवला सुपारी,अरोमा मोमबत्ती, मोमबत्ती पैकेट तथा पर्यावरण संरक्षण की थैली भेंट की गई। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सभी उपहारो की सराहना की और बंदियो द्वारा किए गए इस नवाचार की भरपूर सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट की गई टेबल मैट का उपयोग वे पूजा अर्चना में करेंगे।

सम्पादकीय

मध्यप्रदेश सहित देश में मिल रहा जैविक खेती को बढ़ावा

केंद्र सरकार सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) योजना लागू कर रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन और कटाई के बाद प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक एंड-टू-एंड समर्थन पर जोर देती हैं। पीकेवीवाई के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3 साल की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक आदानों के लिए 3 वर्षों के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं। निर्यात बाजार के विकास के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी द्वारा तृतीय पक्ष प्रमाणन। एनपीओपी प्रमाणन योजना के अंतर्गत जैविक उत्पादों के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार और निर्यात आवश्यकताओं जैसे सभी चरणों में उत्पादन और संचालन गतिविधियों को कवर किया जाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया) जिसमें हितधारक (किसान/उत्पादक सहित) एक-दूसरे के उत्पादन प्रथाओं का आकलन, निरीक्षण और सत्यापन करके और सामूहिक रूप से उत्पाद को जैविक घोषित करके पीजीएस-इंडिया प्रमाणन के संचालन के बारे में निर्णय लेने में शामिल होते हैं। पीजीएस-इंडिया प्रमाणन घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए है। पीकेवीवाई के अंतर्गत एनपीओपी प्रमाणीकरण और पीजीएस-इंडिया प्रमाणीकरण के अंतर्गत कवर किया गया कुल बढ़ता हुआ राज्यवार जैविक क्षेत्र 59.74 लाख हेक्टेयर है। पीकेवीवाई के अंतर्गत मूल्य संवर्धन, विपणन और प्रचार की सुविधा के लिए 3 वर्षों के लिए 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। किसानों के लिए पीकेवीवाई के अंतर्गत 3 वर्षों के लिए 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रमाणन और प्रशिक्षण तथा हैंडहोल्डिंग और क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। जबकि एमओवीसीडीएनईआर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और प्रमाणीकरण के लिए 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य अपने क्षेत्र में या अन्य राज्यों के प्रमुख बाजारों में सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, क्रेता-विक्रेता बैठकें, प्रदर्शनियां, व्यापार मेले और जैविक उत्सव आयोजित करते हैं। सरकार ने किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को जैविक उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में वेब पोर्टल- www.Jaivikkheti.in/ विकसित किया है, ताकि उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद मिल सके। जैविक खेती पोर्टल के अंतर्गत कुल 6.22 लाख किसान पंजीकृत हैं।

सियासी गहमागहमी

शराब पर शुरू की भाजपा नेता ने सियासत

देवास शहर में शराब पर सियासत शुरू हुई है। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने लिखा कि मां देववासिनी की नगरी देवास को बनाएंगे शराब मुक्त नगरी। इस पोस्ट के प्रसारित होते ही शहर में चर्चा शुरू हुई। कुछ ठेकेदार भी सकते में हैं। जाहिर है कि सांसद सोलंकी पहले भी जुए-सट्टे के मामले को लेकर इस तरह की पोस्ट कर चुके हैं। शराब पर शुरू हुई सियासत की स्क्रिप्ट नई नहीं है। यह पहले से लिखी जा रही है, लेकिन अब जबकि भाजपा में सबके सुर अलग हो गए हैं तो सांसद अपनी टीम मजबूत करने में जुटे हैं। इसके चलते इस पूरे चुनाव में उनका रूख अलग ही रहा और खुद की टीम बनाकर काम किया। भाजपा में चल रही खींचतान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक देवास जिले में पिछले दिनों हुए शराब के ठेकों में कुछ नेताओं की संलिप्तता की चर्चा है। इसकी पार्टी में भी चर्चा है। हालांकि सांसद इस बात को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ता इस तरह के काम नहीं करता।

आखिर किसके सिर सजेगा अध्यक्ष का सेहरा

नए साल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष की ताजपोशी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दिल्ली चुनाव हो गये हैं और सरकार भी भाजपा की बन गई है। ऐसे में आशंका है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जायेगा। क्योंकि दिल्ली से लेकर भोपाल तक कई संगठनात्मक बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर रायशुमारी हुई है। फिलहाल खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वह 2020 से लेकर 2025 तक की पारी खेल चुके हैं। अध्यक्ष पद को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही है, क्योंकि इस पद के लिए कई नेता दावेदार नजर आ रहे हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते है। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद।

प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध - दिल्ली की प्रगति और दिल्लीवासियों के अधिकारों की यह लड़ाई जारी रहेगी।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

भाजपा मौन और गुंडे मुखर।
दिल भर आता है, आँखें शर्म से झुक जाती है, आखिर क्या हो गया है मेरे मध्य प्रदेश को।

सरेआम एक बेटी पर छिकरे कसे जाते है, परिजन लफंगों को रोकते है तो हमला कर दिया जाता है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

आम आदमी के हीरो केजरीवाल को पछाड़ कर सियासी किंग बनेंगे प्रवेश वर्मा

समता पाठक/जगत प्रवाह

नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का नाम एक दम से चर्चा में आ गया है। आप के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा 2013 से अपनी सियासी सफर की शुरुआत बीजेपी के साथ की थी। अपने तल्ख तेवर और बयानों के लिए पहचाने जाने वाले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का जन्म 07 नवंबर 1977 को दिल्ली में हुआ था। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। सियासत का अनुभव और पाठशाला वो अपने घर से ही सीख चुके थे। प्रवेश वर्मा ने बचपन से ही सत्ता और सरकार को काफी करीब से देखा है। प्रवेश का एमपी से भी गहरा रिश्ता है। उनकी धार जिले में ससुराल है। उनके ससुर विक्रम वर्मा बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। चुनाव प्रचार अभियान के बीच भी ससुराल वालों ने दामाद की जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। जब कोई व्यक्ति सफल होता है, उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली होती है, तो हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर संबंधित शख्स ने अपनी स्कूलिंग कहां से की है, क्योंकि अधिकांश सफलताओं में शिक्षा और संस्कार का बड़ा योगदान होता है। तो यहां, हम आपको बता दें, प्रवेश की स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम से हुई है। उच्च शिक्षा के लिए फिर किरोड़ीमल कॉलेज गए। यहां से स्नातक की डिग्री पूरी की। इसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए की डिग्री हासिल की है। प्रवेश वर्मा सफलता के चाहे जिस भी शिखर पर रहें, लेकिन दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली महरौली विधानसभा सीट को वो कभी नहीं भूल पाएंगे। इस सीट से प्रवेश का गहरा नाता रहा है क्योंकि इसी सीट पर 2013 में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री को हराकर लोगों के बीच चर्चा में आ गए थे। फिर 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने पश्चिमी दिल्ली से जीत हासिल की। इस जीत ने उनकी राजनीतिक छवि को और भी विस्तार दिया। बीजेपी में मजबूत पकड़ बनाई। इस बीच प्रवेश पार्टी में जितने सक्रिय रहे, उतने ही जनता के बीच भी लोकप्रिय रहे। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को हराकर बीजेपी को मजबूत किया है। प्रवेश वर्मा अपने तल्ख बयानों के लिए अक्सर लोगों के बीच चर्चित रहते हैं। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान इनके बयानों की खूब चर्चा रही। उन्होंने अपने एक बयान में का विरोध करने वाले विशेष समुदाय के व्यापार के बहिष्कार करने की बात कही थी। इसके बाद बीते साल कुछ साल पहले छठ पूजा से पहले एक सरकारी अधिकारी के साथ उनके विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

मोदी सरकार का आम बजट

एक बार फिर छला गया मिडिल क्लास, मोदी के मिशन नारी, युवा, किसान और गरीब के लिए क्या?

कमलनाथ
(मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता)

मोदी सरकार ने देश के लिए आम बजट पेश कर दिया है। बजट में मोदी सरकार ने तमाम तरह की उपलब्धियों को गिनाकर बजट को महिमा मंडित किया है। खासकर देश के मिडिल क्लास को तो ऐसे परिभाषित किया है जैसे इस क्लास के लिए सरकार ने पूरा खजाना ही लूटा दिया है। दूसरी तरफ देखा जाये तो मोदी का मिशन है कि नारी, युवा, किसान और गरीब के लिए कल्याण करना। लेकिन सवाल उठता है कि इनके लिए बजट में क्या है?

एससी और एसटी की पांच लाख महिला उद्यमियों के लिए अगले पांच साल के दौरान दो करोड़ रुपये तक के टर्म लोन की बात कही गई है। लोन मिलने में महिला उद्यमियों को काफी दिक्कत होती है, बिज़नेस चलाने में महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत होती है। इस बजट में महिलाओं के लिए इसके अलावा अलग से कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। देश के अंदर महिलाओं की आधी आबादी है। सवाल फिर वहीं है कि कितनी महिलाएं अपना स्टार्टअप लगाना चाहती हैं? क्या सभी महिलाएं उद्यमी बनती हैं। बजट में ऐसी घोषणाओं होनी चाहिए थी कि जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करती।

युवाओं के लिए बजट में कोई खास नहीं किया गया है। युवा चाहते हैं सरकार उन्हें देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मुहैया कराए जाए, इसके साथ ही युवाओं को देश से पलायन कर दूसरे देशों में जाना बड़ी समस्या है। युवा बेहतर भविष्य की आस में दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। युवाओं को बजट में यह भी उम्मीद थी कि सरकार कुछ ऐसी अहम घोषणाएं करेगी, जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था दोनों को तेजी से बढ़ावा मिल सके। लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई जिससे लगे कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए खास किया है। सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की है। सरकार का ध्यान इस बात पर होना चाहिए था कि देश के अंदर रोजगार कैसे पैदा हों।

मोदी सरकार गरीबी की बड़ी हितैषी बताती है लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किये हैं। मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना जस का तस रखा है। गरीबों के कल्याण का सिर्फ दिखावा भर है।

किसानों की अनदेखी

बजट में किसानी को तो बिल्कुल अलग-थलग ही कर दिया है। देश में 70 फीसदी लोग किसानी से जुड़े हैं। उनकी आजीविका खेती है। लेकिन इस सबसे बड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया। वर्षों से एमएसपी को लेकर बवाल मचा हुआ है। किसानों की मांग थी कि एमएसपी को लागू किया जाये। लेकिन इस पर तो बात ही नहीं की गई। दूसरी तरफ देखा जाये तो किसान ही सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबा है। किसानों को आस थी कि कर्जमाफी की बात की जायेगी। लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 03 लाख से 05 लाख बढ़ाकर उन्हें और कर्जदार बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। कांग्रेस शासन में किसानों का लगभग 70 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया था। इसके अलावा भी कांग्रेस सरकार के हित में फैसले लेती थी। खेती घाटे का सौदा होने से किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। क्या इसके रोकथाम के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है?

मध्यम वर्ग को राहत के नाम पर वाहवाही

यह भी सच है कि जब भी देश में या प्रदेश में बजट की बात आती है मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा दवाब भी मिडिल क्लास पर पड़ा है। वह चाहे मंहगाई को लेकर हो या बेरोजगारी को लेकर हो। देश के अंदर मध्यम वर्ग की संख्या लगभग 50 करोड़ है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस क्लास को सुनियोजित ढंग से छला जा रहा है। इस बार भी सालाना 12.75 लाख तक आय वालों को आयकर में छूट देने के नाम पर छला गया है। बड़ा सवाल है कि लगभग 12 लाख की आमदनी वाले को मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग माना है। यानि जिसकी एक लाख रूपये महीने की कमाई होगी वह मध्यम वर्ग का होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि एक लाख कमाने वाला व्यक्ति कैसे मिडिल वर्ग का होगा। वह तो अपर क्लास का ही माना जायेगा। तो फिर यह राहत किसके लिए है? एक तरफ मोदी सरकार देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है और एक लाख आय वाले को मध्यम वर्ग मान रही है। कितना बड़ा छलावा है। हम जानते हैं कि देश की कुल 140 करोड़ आबादी वाले देश में केवल 12 करोड़ लोग ही आयकर दाता

हैं, जिसमें से भी 08 करोड़ लोग उच्च आय वाले हैं। केवल 04 करोड़ लोग ही मध्यम वर्ग के माने जाते हैं। उनमें भी कई तरह के विरोधाभास हैं। फिर इस बजट को कैसे मध्यम वर्ग के लिए वरदान माना जा सकता है।

गोली के घाव पर पट्टी!

राहुल गांधी जी ने कहा, "गोली के घाव पर पट्टी! वैश्विक अनिश्चितता के बीच, हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता थी। लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग से 54.18 लाख करोड़ रुपये आयकर के रूप में वसूले हैं और अब 12 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है, जिसके अनुसार वित्त मंत्री खुद कह रही हैं कि इससे प्रति वर्ष 80,000 रुपये की बचत होगी। यानी हर महीने केवल 6,666 रुपये! उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी खामियों को छिपाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में बदल दिया है। कई अन्य घोषणाएं भी इसी तरह की थीं।

मध्यप्रदेश में बजट में मिला झुनझुना

बजट में मध्य प्रदेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और नागरिकों की भलाई के लिए जरूरी थे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही लचर है और प्रदेश लगातार कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है। राज्य के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में प्रदेश के युवाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं किया।

कांग्रेस और बीजेपी के शासन में अंतर

मोदी सरकार अमीरों और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हितों के लिये काम करती है, कांग्रेस की सरकार गरीबों, किसानों मजदूरों सहित आम जनता के हितों के लिये काम करती है। कांग्रेस की सरकार पूंजीपतियों से पैसा छीनकर, गरीबों, मजदूरों सहित आम जनता को अमीर बनाती है। मोदी सरकार गरीबों के ऊपर टैक्स लगाती है, कांग्रेस की सरकार अमीरों के उपर टैक्स लगाती है। मोदी सरकार देश के कल कारखानों को बेचकर नौजवानों को बेरोजगार बनाती है, कांग्रेस की सरकार नये कल कारखाने खोलकर नौजवानों को रोजगार देती है। मोदी सरकार मँहगाई के दौर में भी टैक्स बढाकर, मँहगाई का बोझ आम जनता के उपर डालती है, पर कांग्रेस मँहगाई पर सब्सिडी देकर उसका बोझ आम जनता के उपर नही डालती है। भाजपा एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है, जबकि कांग्रेस एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। भाजपा सरकार के हस्तक्षेप को कम करने और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, जबकि कांग्रेस सामाजिक न्याय और गरीबों के कल्याण के लिए सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ावा देती है। बेरोजगारी दूर करने के लिये कांग्रेस ने सरकारी संस्थान खोले। मोदी सरकार के लिये नये संस्थान खोलना तो दूर उन्हें चलाने वालों को नकारा, कामचोर आदि बताकर बेचने में लगी हुई है तथा बेरोजगारी के आँकड़े प्रकाशित करने पर रोक लगा रखी है।

अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'अमेरिका प्रथम' अभियान पर अमल शुरू कर दिया है। ट्रंप ने चुनाव से पहले गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे भारत समेत अन्य देशों के नागरिकों को वापस भेजने का सिलसिला तेज कर दिया है। इस क्रम में अमेरिकी शहर टेक्सास से 205 ऐसे भारतीयों को सैन्य विमान में लादकर अमृतसर में लाया गया है, जो गैर-कानूनी ढंग से अमेरिका में रह रहे थे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि अवैध अप्रवासियों का भारत स्वागत करेगा। इस पहली खेप में भेजे गए 205 प्रवासियों का भारत में रिहाईश का पूरा डाटा जांच करने के बाद लिया गया है। जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से इस मुद्दे पर सहमति 23 जनवरी 2025 को ही बन गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत में भरोसा दिया था कि जो सही होगा उसे स्वीकार करेंगे। अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट (आईसीई) की सूची के अनुसार ऐसे करीब 20,427 भारतीयों की सूची हैं, जो अवैध प्रवासियों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 17,940 भारतीयों के मूल निवासी होने के पतों का दस्तावेजी सत्यापन भी हो चुका है। इन्हें भी अमेरिका से निकालने की कार्यवाही चल रही हैं। हालांकि एक निजी एजेंसी के अनुसार अमेरिका में करीब 7.25 लाख भारतीय अवैध ढंग से रह रहे हैं।

हालांकि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निकाले जाने की बात कोई नई नहीं है। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के दौरान 1100 लोगों को चार्टड विमान से भेज चुका है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत समेत अन्य देशों के चार लाख से भी अधिक अप्रवासी निकाले गए थे। अमेरिका अब तक चार छोटे देशों ग्वाटेमाला, होंडूरास, इक्वाडोर और पेरू के अवैध प्रवासियों को निकाल चुका है। भारत पांचवां देश हैं, जहां के अवैध प्रवासियों को निकाला गया है। अमेरिका ने मैक्सिको और कोलंबिया के भी अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान में लादकर भेजा था। परंतु इन देशों की सरकारों ने विमान को अपने देशों की सीमा के भीतर उतरने की मंजूरी नहीं दी थी। बाद में इन्हें सीमा पर उतारने की सहमति बन गई थी। अमेरिका में वैध एवं अवैध तरीकों से बसने की इच्छा रखने वालों में भारत के बाद दूसरे पायदान पर चीनी नागरिक हैं। इसके बाद अल-साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, फिलीपींस, मैक्सिको और वियतनाम के प्रवासी हैं। दरअसल अमेरिका अवसरों और उपलब्धियों से भरा देश माना जाता है। इसलिए लोग बेहतर और सुविधाजनक जीवन जीने की दृष्टि से अमेरिका में स्थाई तौर से बसने की लालसा रखते हैं। किंतु अब लगता है अमेरिका में विदेशी प्रवासियों के रास्ते बंद हो रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने जन्मजात नागरिकता पर भी रोक लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है।

ट्रंप द्वारा जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश के पहले तक अमेरिका में किसी भी देश के प्रवासी दंपत्ति के जन्मे शिशु को जन्मजात नागरिकता स्वतः मिल जाती थी। यह प्रावधान तब भी था, जब उनकी माता अवैध रूप से देश में रह रही हो और पिता भी वैध स्थायी निवासी न हो। ट्रंप द्वारा जन्मजात नागरिकता पर प्रतिबंध के बाद सबसे अधिक परेशानी उन महिलाओं को हो रही है, जो अमेरिका में शरणार्थी या अवैध प्रवासी के रूप में रह रही हैं। वे सवाल उठा रही हैं कि उनकी कोख में पल रहे मासूम शिशु का क्या दोष है? ट्रंप के प्रतिबंधित आदेश के अनुसार वही जन्मजात बच्चे अमेरिकी नागरिकता के पात्र होंगे जिनके माता या पिता अमेरिकी नागरिक हैं। कुछ राज्यों में अदालत के आदेश के चलते जन्मजात नागरिकता पर प्रतिबंध जरूर लग गया है, लेकिन ट्रंप ने इस आदेश के विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। ट्रंप ने कड़ा रुख व्यक्त करते हुए कहा है, 'हम पीछे नहीं हटेंगे।' अमेरिकी न्याय विभाग दावा कर रहा है कि जन्मजात नागरिकता खत्म करना अमेरिकी हितों के अनुरूप है। इससे लगता है, देर-सबेर जन्मजात नागरिकता खत्म करने का कानून संपूर्ण अमेरिका में लागू हो जाएगा। वैसे भी अमेरिका में भारतीयों तथा अन्य वैध-अवैध प्रवासियों के विरुद्ध धुर दक्षिण पंथियों का आंदोलन 'अमेरिका प्रथम' एक अभियान के रूप में सक्रिय है। यही नहीं यह आंदोलन उग्र रूप में बदलकर 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' अर्थात 'अमेरिका को फिर से महान बनाएं' जाने की मानसिकता के चलते नस्लीय तनाव के रूप में भी देखने में आ रहा है।

अवैध प्रवासियों के संदर्भ में अमेरिका को अपने गिरेवान में भी झांकने की जरूरत है। क्योंकि चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती, का दावा करने वाला देश अवैध तरीके से आने वाले प्रवासियों पर लगाम लगाने में अब तक नाकाम रहा है। इसीलिए अमेरिका को मूलतः अप्रवासियों का देश माना जाता है। भारत के साथ अन्य देशों के लोग भी फर्जी दस्तावेजों और गैर-कानूनी तरीकों के आधार पर अमेरिकी सीमाओं के पार चले जाते हैं? आखिर डंकी रूट के जरिए अमेरिका में ही क्यों सबसे ज्यादा लोग प्रवेश करने में सफलता पा लेते हैं? इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिका में कुशल एवं अकुशल कामगारों की हमेशा जरूरत रहती है। इसलिए कंपनियां अवैध तरीकों के जरिए विदेशियों को लाकर उसी तरह बसाती हैं, जिस तरह भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बसाने का प्रबंध किया जाता है। अमेरिका सरकार का दावा है कि बीते पांच साल में दो लाख से ज्यादा भारतीय चोरी-छिपे अमेरिका में घुसने के प्रयास में पकड़े गए हैं। इनमें से कुछ वापस हो गए तो कुछ हिरासत में रहकर रिहाई के प्रयास में हैं। जबकि डंकी रुट का पर्याय बनी घुसपैठ की कोशिशें अत्यंत जोखिम भरी होने के साथ जानलेवा भी हैं। अनेक भारतीय युवा नौकरी व कारोबार करने की ललक में अपनी पैतृक जमीन बेचकर डंकी रुट से अमेरिका जाने का जोखिम उठाकर बर्बाद हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका में चालक (ड्राइवर) जैसी छोटी नौकरी में भी करीब साढ़े तीन लाख रुपए का वेतन प्रतिमाह मिलता है। इसीलिए हरियाणा और पंजाब के सैंकड़ों युवा डंकी रुट के मोहजाल में आकर स्वंय के साथ समूचे परिवार की आर्थिक बद्हाली की कहानी लिख चुके हैं। अतएव युवाओं को ही नहीं उन अभिभावकों को अमेरिकी दीवानगी से बचने की जरूरत है, जो अपनी संतान का उज्जवल भविश्य अमेरिकी चकाचैंध में देख रहे हैं।

प्रवासियों का देश अमेरिका

अमेरिका की कुल जनसंख्या करीब 33 करोड़ है। इस आबादी की तुलना में उसका भू-क्षेत्र बहुत बड़ा, यानी 98,33,520 वर्ग किमी है। इतने बड़े भू-लोक के मालिक अमेरिका के साथ विडंबना है कि 15वीं शताब्दी तक अमेरिका की कोई स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान नहीं थी। दुनिया केवल एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों से ही परिचित थी। 1492 में नई दुनिया की खोज में निकले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। हालांकि कोलंबस अमेरिका की बजाय भारत की खोज में निकला था। लेकिन रास्ता भटक कर वह अमेरिका पहुंच गया। वहां के लोगों को उसने 'रेड इंडियन' कहकर पुकारा। क्योंकि ये तांबई रंग के थे और प्राचीन भारतीयों से इनकी नस्ल मेल खाती थी। हालांकि इस क्षेत्र में आने के बाद कोलंबस जान गया था कि वह भारत की बजाय कहीं और पहुंच गया है। बावजूद उसका इस दुर्लभ क्षेत्र में आगमन इतिहास व भूगोल के लिए एक क्रांतिकारी पहल थी। कालांतर में यहां अनेक औपनिवेशिक शक्तियों ने अतिक्रमण किया। 17वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया और अन्य प्रशांत महासागरीय द्वीप समूहों की खोज कप्तान जेम्स कुक ने की। जेम्स ने यहां अनेक प्रवासियों की बस्तियों को आबाद किया।

इसी क्रम में 1607 में अंग्रेजों ने वर्जीनिया में अपनी बस्तियाँ बसाईं। इसके बाद फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड ने उपनिवेश बनाए। 1733 तक यहां 13 बस्तियां अस्तित्व में आ गईं। इन सब पर ब्रिटेन का प्रभुत्व कायम हो गया। 1775 में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया। 4 जुलाई 1776 में जार्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी जनता ने विजय प्राप्त कर ली और संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन कर स्वतंत्र और शक्तिषाली राष्ट्र के रूप में वह अस्तित्व में आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका के इतिहास व अस्तित्व में दुनिया के प्रवासियों का बड़ा योगदान रहा है। साथ ही यहां एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि अमेरिका महाद्वीप के जो रेड इंडियन नस्ल के मूल निवासी थे, वे हाशिये पर चले गए। गोया, मूल अमेरिकी तो वंचित रह गए, अलबत्ता विदेशी-प्रवासी प्रतिभावान किंतु चालाक अमेरिका के मालिक बन बैठे। इस विरोधाभास का मूल्यांकन करके ही ट्रंप चिंतित हैं कि आईटी टेक्नोक्रेट के बहाने जो आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिकी संस्थाओं व कंपनियों पर प्रभावी होते जा रहे हैं, वे मूल-अमेरिकियों के लिए अमेरिकी संस्थाओं में बेदखली और बेरोजगारी का कारण भी बन रहे हैं। इसी लिहाज में ट्रंप अमेरिका-फर्स्ट की नीति को महत्व दे रहे हैं।

इस दृष्टिकोण से यदि वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका का नृजातीय रूप में मूल्यांकन करें तो पता चलता है कि यहां मूल अमेरिकियों, मसलन रेड इंडियनों की आबादी महज 2.7 प्रतिशत ही रह गई है, शेष 97.7 फीसदी भूमि पर यूरोप, अफ्रीका और एशिया से आ बसे लोगों का कब्जा है। इसमें रेड इंडियन के साथ नवाजो और चरूकी जनजातीय लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें अधिकांश लोग अब अपनी संस्कृति से कट गए हैं। ज्यादातर ने आधुनिक अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया है। लेकिन नस्लीय भेदभाव के चलते अमेरीकी समाज इन्हें दोयम दृष्टि से देखता है। इस कारण ये आधुनिक सुविधाओं से लगभग वंचित व उपेक्षित हैं। अभावग्रस्त यही लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के लिए अमेरिका में अलग मंत्रालय खोलकर इनके कल्याण के लिए पहल की जा रही है। अमेरिका में कुल आबादी में से 13.66 फीसदी लोग गरीबी-रेखा के नीचे रहने को विवश हैं। इन्हीं लोगों में सर्वाधिक बेरोजगारी है। राष्ट्रपति ट्रंप शायद ऐसे ही लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए जन्मजात नागरिकता और वीजा संबंधी नियमों को कठोर बना रहे हैं, जिससे गैर-अमेरिकियों के लिए रोजगार के रास्ते बंद हो जाएं और स्थानीय लोगों के लिए खुल जाएं। लेकिन आज अमेरिका जिस विकास और समृद्धि को प्राप्त कर पूंजीपति व शक्ति-संपन्न राष्ट्र बना दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाए बैठा है, उसकी पृष्ठभूमि में दुनिया के प्रवासियों का ही प्रमुख योगदान है। लिहाजा ट्रंप के प्रवासी भारतीयों समेत अन्य प्रवासियों को अमेरिका में ही बसाए रखने के नीति और उपाय बदस्तूर रखने चाहिए।

लॉस एंजिल्स अग्नि से मिलती है सीख

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

लॉस एंजेलिस में लगी आग को अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक आग माना जा रहा है। कई जंगल जलकर स्वाहा हो गए हैं। कई लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं। अनुमान है कि इस आग के चलते करीब 11 से 13 लाख करोड़ तक का नुकसान हुआ है। न केवल अमेरिका के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास में यह जंगल का आग सबसे वैज्ञानिक, सबसे विनाशकारी और डरावना साबित हुआ है। इस महाविनाश और भारी जन-धन की क्षति ने साबित कर दिया है कि दुनिया की एक महाशक्ति भी कुदरत के रौद्र के सामने बौनी ही साबित हुई है। दुनिया का सुपर पावर बेबस नजर आ रहा था। प्रकृति के रौद्र रूप के सामने आखिर किसका वश चलता है? अनियमित विकास, पर्यावरण की घोर अनदेखी एवं भौतिकतावादी सोच इस आग का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया को सुरक्षा देने वाला और खुद को शक्तिशाली समझने वाला देश खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया। अमेरिका के विकास की होड़ एवं प्रौद्योगिकी की दौड़ पूरी मानव जाति को ऐसे जगह ले जा रही है, जहां से लौटना मुश्किल हो गया है। इसका अनुशरण भारत सहित दूसरे देश भी कर रहे हैं। जंगलों में आग की ऐसी खबरें पहले भी कई बार सामने आई हैं। पिछले साल भारत में उत्तराखंड के जंगलों में आग ने ऐसी ही तबाही मचाई थी। अल्मोड़ा के जंगलों में आग 41 दिनों तक धधकती रही थी, इस दौरान कई हैक्टेयर फसल बर्बाद हो गई थी। मानव-जनित जलवायु परिवर्तन ने दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षावनों में आग लगती रही है।

हालांकि, लॉस एंजिल्स के आग लगने का ठोस कारण अभी तक पता नहीं चला है। कुछ जानकार बिजली गिरने के चलते आग लगने को संभावित कारण बता रहे हैं जबकि कुछ इससे इनकार भी कर रहे हैं। लेकिन लॉस ऐंजिलिस आग को एक्सपर्ट क्लाइमेट चेंज का दुष्परिणाम बता रहे हैं। तेल, कोयला और गैस के जलने से निकलने वाली वो गैसें जिनसे धरती गरम होती हैं, ने जंगल की आग को और खतरनाक बना दिया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कैलिफोर्निया में पतझड़/ठंड में बारिश के मौसम की शुरुआत को लेट कर दिया है। लॉस ऐंजिलिस तो जुलाई 2024 के बाद से ही बारिश की कमी का सामना कर रहा है। इलाका 150 वर्षों में दूसरे सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहा है। इसी तरह दक्षिणी कैलिफोर्निया में 1 अक्टूबर से अबतक औसत बारिश में 10 प्रतिशत की गिरावट हुई है। कई जगहों पर 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं बह रही थीं। इन स्थितियों ने आग को और विकराल कर दिया था। साल के शुरुआत में लॉस ऐंजिलिस में तेज हवाएं सामान्य होती हैं लेकिन शुष्क मौसम और क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगल की आग और ज्यादा खतरनाक हो गई थीं।

हकीकत है कि जंगलों में 95 फीसदी आग इंसानों द्वारा ही लगायी जाती है। एक शोध में यह भी देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगल की आग में कम से कम क्रमशः तीन गुना और दोगुनी बढ़ोतरी हुई। बीते 150 साल में वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों में हुई बढ़ोतरी के मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। आज अमेरिका विकास की चरम अवस्था पार कर चुका है। दूसरे देश भी इस विकास की होड़ में लगे हुए हैं। जब तक प्रकृति डराती नहीं विकास की राहें ऐसे ही बेतहाशा एवं अनियंत्रित आगे बढ़ती रहती हैं। धरती पर मंडराते इसी संकट का प्रतीक है यह आग। यह सिर्फ अमेरिका का संकट नहीं है। यह दुनियाभर को हिला देने वाली आपदा है।

हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसी प्राकृतिक चरम स्थितियों और मानवीय लापरवाही ने जंगल की आग की आपदा में योगदान देते है जो गर्मियों के दौरान एक आम घटना है। लोगों और सरकार ने पहले कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे आम तौर पर निवास क्षेत्रों से बहुत दूर होते हैं लेकिन जंगल की आग से पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को अनदेखा करना एक ऐसी गलती है जो हम लगातार कर रहे हैं। आग लगने की घटना सामने आने के बाद मीडिया में यह खबर आई कि इलाके में पानी भंडार करने वाले अधिकतर हॉज सूखे हुए थे। अब समय आ गया है कि सरकार जल्द से जल्द ऐसी आग से निपटने के लिए कदम उठाए और अगर नागरिकों को सांस लेने के लिए स्वच्छ, ताजी हवा चाहिए और अपने जंगल, जानवर और पर्यावरण को बचाना है तो उन्हें रोकने के लिए उचित कदम उठाने के लिए जल्द से जल्द दबाव डालना चाहिए।

हौसलों को उड़ान देने का अवसर है परीक्षा

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

आज हम बात करेंगे परीक्षाओं के बारे में, जो कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होती हैं। कुछ ही दिनों में स्कूलों में फाइनल परीक्षा शुरू होना है। ये अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम है। परीक्षाएं केवल विद्यार्थियों की नहीं होतीं, यह माता-पिता और शिक्षकों की भी होती है, क्योंकि विद्यार्थी के विकास में इनका भी बड़ा योगदान है। ऐसे में सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को प्रेरित करें और परीक्षा के दौरान उन्हें सकारात्मक माहौल दें। हम बच्चों को थोड़ा सा सहयोग करके उन्हें सफलता के शिखर की ओर अग्रसर कर सकते हैं। हर परीक्षा एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत। ये अपने अंदर छिपे हुनर को उजागर करने का मौका है। ये वो फल है जब हम अपनी मेहनत और लगन का परीक्षण करते हैं। याद रखिए, हर सफलता का आधार मेहनत ही होती है। आज के युवाओं के लिए परीक्षाएं सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने का मंच है। ये वो कदम है जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। याद रखिए, हर इंसान खास होता है और हर एक की अपनी अलग काबिलियत होती है। आपको बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है।

बच्चों के लिए सफलता के सुपर सिक्स

- विषयों की जटिलता के अनुसार टाइम टेबल बनाएं।
- छोटे-छोटे पॉइंटर्स लिखकर रिविजन नोट्स तैयार करें।
- स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त नींद लें।
- खुद पर विश्वास रखें और सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प लें।
- आप अकेले नहीं हैं। माता-पिता, शिक्षक और दोस्त आपके साथ हैं।
- याद रखें परीक्षाएं जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हैं।

माता-पिता को सलाह

- अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए बच्चों पर दबाव न बनाएं बल्कि उन्हें सहयोग दें और प्रेरित करें।
- बच्चों के साथ समय बिताएं। परीक्षा की तैयारी पर चर्चा करें और बताएं कि आप उन पर कितना विश्वास करते हैं।
- परीक्षाओं के दौरान बच्चों को पौष्टिक आहार दें, जिससे वे स्वस्थ रहें और मेहनत कर सकें।
- बच्चों को पढ़ाई के बीच थोड़ा खेलकूद और मनोरंजन भी करने दें, जिससे वे तनावमुक्त रहें।
- बच्चों को समझाएं कि परीक्षा से डरें नहीं, परिणाम जो भी हो आप हमेशा उनके साथ हैं।

शिक्षक यह प्रयास करें

- बच्चों की कमजोरियां दूर करने में उनकी मदद करें। कठिन विषयों में उन्हें नोट्स बनाकर दें।
- बच्चों के मॉक टेस्ट लें, जिससे उनमें परीक्षा का भय कम हो और वे अपनी गलतियों को पहचानकर उनमें सुधार करें।
- हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसकी समझ और काबिलियत के अनुसार उसे लक्ष्य दें।
- समय प्रबंधन, पढ़ने के दौरान ध्यान केंद्रित करने और विषयवार टाइम टेबल बनाने के लिए उन्हें मार्गदर्शित करें।
- विद्यार्थियों को पेपर हल करने की तकनीक जरूर सीखाएं, जिससे वे अपनी पूरी काबिलियत का प्रदर्शन कर सकें।

बच्चों, याद रखो परीक्षाएं एक नई शुरूआत का द्वार हैं। परीक्षाएं जीवन का अंत नहीं बल्कि अवसर हैं। हर परीक्षा एक नया मौका है। खुद को साबित करने का। चिंता मत करो, बस विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, जो तुम्हें हर मुश्किल से पार लगा सकती है। पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करो, और परीक्षा हॉल में जाकर बेझिझक अपना सर्वश्रेष्ठ दो

सभी राज्यों में भाजपा सरकार आने से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उठने लगे सवाल

(पेज 1 से जारी)

22 सीटों पर सिमट गई आप

70 सीटों वाली दिल्ली में जहां बीजेपी को 48 सीटों के साथ बहुमत मिला वहीं यहां सत्ता में रही आम आदमी पार्टी 22 सीटों में ही सिमट गई। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो जहां बीजेपी को 45.56 फ़ीसदी वोट मिले वहीं आम आदमी पार्टी को 43.57 फ़ीसदी वोट मिले। यहां तीसरे खेमे के रूप में कांग्रेस थी जो एक भी सीट पर कब्ज़ा करने में नाकाम रही। हालांकि उसका वोट प्रतिशत 6.34 फ़ीसदी रहा। ये 2020 के चुनावों में उसके प्रदर्शन से बेहतर था, जब उसे 4.63 फ़ीसदी वोट मिले थे।

ऐसे समझो चुनावी गणित का आंकड़ा

इस बार के चुनाव में दिल्ली की कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हार का कारण बनी। इन सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर कांग्रेस के वोटों से कम है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर साथ में मैदान में उतरी थीं। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ने अकेले ही चुनावी रण में उतरने का फ़ैसला किया। चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों ने जमकर एक-दूसरे पर तंज़ कसे। लेकिन चुनाव नतीजे देखने के बाद, ऐसा लगता है कि दोनों ने अगर एकसाथ चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया होता और दोनों के वोट एक होते, तो एक टीम के तौर पर उन्हें जीत मिल सकती थी।

यह है मुख्य हार के कारण

नई दिल्ली- इस सीट से खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मैदान में थे। उन्हें बीजेपी के प्रवेश सिंह वर्मा ने 4,089 वोटों से शिकस्त दी। केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को मात देकर इस सीट से जीत हासिल की थी और लगातार तीन बार यहां से विधायक रहे। वहीं उन्हें हराने वाले प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और दो बार पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहे हैं।

जंगपुरा- इस हाई प्रोफ़ाइल सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ़ से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया उम्मीदवार थे। उन्हें केवल 675 वोटों से हार मिली। यहां से जीत बीजेपी के तरविन्दर सिंह मारवाह की हुई। इस सीट पर कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही। उसके उम्मीदवार फ़रहाद सूरी को 7,350 वोट मिले। मनीष सिसोदिया 2013 से लगातार तीन बार पटपड़गंज सीट से विधायक थे। चुनाव से पहले उन्होंने अपनी सीट बदल ली थी। 2024 में पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये प्रयोग न तो अवध ओझा के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ न ही मनीष सिसोदिया के लिए। बीते तीन बार से जंगपुरा विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के नाम रही है। 2013 में यहां से मनिन्दर सिंह धीर ने जीत हासिल की थी, जबकि 2015 और 2020 में यहां प्रवीण कुमार को जीत मिली।

बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में आये बड़े-बड़े उद्योगपति

-अमित राय

जगत प्रवाह. कोलकाता। ग्लोबल समिट के उद्घाटन कार्यक्रम दौरान अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनेता, औद्योगिक और व्यावसायिक दिग्गज, साथ ही सौरव गांगुली जैसी हस्तियां भी शामिल हुईं। मुकेश अंबानी से लेकर सज्जन जिंदल, भूटान के मंत्री से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। सभी ने सार्वजनिक नीतियों और उद्योगों, बुनियादी ढांचे और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ममता सरकार की अटूट प्रतिबद्धताओं की सराहना की। साथ ही कई बड़ी घोषणाएं की गईं और लाखों करोड़ रुपये के निवेश के फैसले लिए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और वादों की घोषणा की और हजारों की संख्या में मौजूद प्रतिनिधियों को बताया कि हम किस तरह सामाजिक सुरक्षा को उद्योग-अनुकूल कदमों के साथ जोड़ते हैं। ताकि व्यापार करने में आसानी हो और बेहतर तालमेल हो। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण बात यह है कि अब से निवेश परियोजनाओं के लिए प्रभावी, एक-स्टॉप और समयबद्ध मंजूरी तंत्र के लिए हमारे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निवेश तालमेल समिति होगी। समिति द्वारा पाक्षिक बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें सभी विभागीय सचिव शामिल होंगे, ताकि 'कोई देरी न हो'। वहीं मुकेश अंबानी ने डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें बंगाल की धरती से जीओ सेवाएं वैश्विक स्तर पर प्रदान की जाएंगी, खुदरा, कारीगर अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के तहत सोनार बांग्ला को सौर बांग्ला बनाया जाएगा। अगले कुछ वर्षों में बंगाल में अपने निवेश को दोगुना करने का मुकेश अंबानी ने वादा किया। कुछ साल पहले, उनका निवेश 2000 करोड़ रुपये था, यह अब 50000 करोड़ है, इसे कुछ वर्षों में दोगुना कर दिया जाएगा। सज्जन जिंदल ने सालबोनी में 16,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 2×800 मेगावाट बिजली संयंत्र की घोषणा की और वादा किया कि भविष्य में इस परियोजना को 16000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 2×800 मेगावाट बिजली संयंत्रों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने 2000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाने का वादा किया और बताया कि वे दुर्गापुर हवाई अड्डे के प्रवेश और विस्तार के लिए परियोजना पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

एम्स भोपाल में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) पर कार्यशाला का आयोजन

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल ने भोपाल जिला के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के कार्यालय के सहयोग से नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं की देखभाल और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जन्म के बाद के महत्वपूर्ण 'स्वर्णिम घंटे' के दौरान नवजात शिशु मामलों का प्रबंधन करने में नर्सिंग अधिकारियों के कौशल को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, "नवजात शिशु की देखभाल में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के हमारे संकल्प का प्रतीक है। नर्सिंग अधिकारियों को उन्नत जीवनदान तकनीकों और ज्ञान से लैस करके हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर नवजात को जीवन के पहले क्षणों में उच्चतम स्तर की देखभाल मिले।" भोपाल जिला के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर तिवारी ने कहा, "यह प्रशिक्षण हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे स्वास्थ्य पेशेवर नवजात शिशु को आपातकाल में को प्रभावी रूप से संभाल पाएंगे।" इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में आवश्यक नवजात शिशु देखभाल प्रथाएँ, बुनियादी जीवनदान तकनीकें, प्रसव के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों को संभालना, और नवजात सुरक्षा में आधुनिक प्रोटोकॉल जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह पहल मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

चैतन्य है मां नर्मदा की धारा, इसके दर्शन से होते हैं सभी धन्यः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. हरदा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मां नर्मदा की धारा चैतन्य है, इसके दर्शन मात्र से ही सभी धन्य हो जाते हैं। आज यहां नर्मदा के तट पर वेदगर्भा घाट का लोकार्पण हुआ है, यहां पर वेद विद्या केंद्र विकसित हो रहा है। नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा है। प्रदेश का सिंचाई रकबा 48 लाख हेक्टेयर से अधिक है, जिसमें से 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मां नर्मदा के जल से सिंचाई होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरदा जिले के छीपानेर में नर्मदा किनारे 'वेदगर्भा घाट' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 316 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमिपूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दौरान हरदा जिले में एक नई आईटीआई संस्था स्वीकृत करने तथा गोंदामांव में सरकारी खर्चे पर सर्वसुविधा युक्त गौशाला स्वीकृत करने की घोषणा की। कार्यक्रम में डारा इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड के मेनेजिंग डायरेक्टर डॉ. पप्पू राम विश्नोई ने इस अवसर पर वेदिक विद्या पीठम् चिचोट के विकास के लिये 1 करोड़ रूपये देने की घोषणा की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी, प्रदेश संगठन मंत्री हितानन्द शर्मा, प्रदेश के सहकारिता तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री गोविन्द महंत, संस्कृत भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयप्रकाश गौतम, अमेरिका से आये समाजसेवी विजय अग्रवाल, डारा इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड के मेनेजिंग डायरेक्टर डॉ. पप्पू राम विश्नोई, ज्ञान मंदिर ब्राजील के अध्यक्ष प्रेमकुमार के अलावा स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति के अध्यक्ष स्वामी नित्य चैतन्य दास जी महाराज भी मौजूद थे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, नर्मदापुरम् के सांसद दर्शन सिंह चौधरी, हरदा के विधायक डॉ. आरके दोगने, टिमरनी विधायक अभिजीत शाह, पूर्वमंत्री कमल पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेन्द्र शाह, उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गेहलोत, नगर पालिका अध्यक्ष हरदा श्रीमती भारती राजू कमेड़िया, पूर्व विधायक संजय शाह, सम्भागायुक्त के.जी. तिवारी, पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ल, कलेक्टर आदित्य सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

316 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण/भूमि पूजन

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)